राजस्थान में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

544
514

National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
D. No.....
Date.....

राजस्थान में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

हमारे देश के संविधान में अपेक्षित है कि देश के सभी 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षित किया जाय। शिक्षा का महत्व देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान के समस्त 26 जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं स्वीकृत केन्द्रों की संख्या लगभग 7,275 है।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में वर्ष 1981 जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत इस प्रकार है :–

1. अजमेर	35.01	प्रतिशत
2. कोटा	31.91	,,
3. जयपुर	31.06	,,
4. झुन्झुनूं	27.81	,,
5. बीकानेर	27.11	,,
6. अलवर	26.09	,,
7. जोधपुर	25.87	,,
8. भरतपुर	25.85	,,
9. गंगानगर	25.56	,,
10. सीकर	24.95	,,

11. सवाई माधोपुर	22.95	प्रतिशत
12. झालावाड़	22.79	,,
13. उदयपुर	21.95	,,
14. चित्तौड़	21.85	,,
15. पाली	21.84	,,
16. चूरू	21.62	,,
17. टौंक	20.26	,,
18. बूंदी	19.94	,,
19. सिरोही	19.09	,,
20. भीलवाड़ा	19.00	,,
21. नागौर	19.25	,,
22. डूंगरपुर	18.42	,,
23. बांसवाड़ा	16.78	,,
24. जैसलमेर	14.73	,,
25. जालौर	13.77	,,
26. बाड़मेर	11.97	,,

राजस्थान में पहले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत समाज शिक्षा के रूप में चलाया जाता था, बाद में किसान क्रियात्मक साक्षरता योजना, अनौपचारिक शिक्षा, पशुपालन आधारित शिक्षा के नाम से प्रसारित किया गया और अब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है किन्तु जनसंख्या में वृद्धि के कारण निरक्षरों की संख्या

और बढ़ रही है। निम्न तालिका से स्थिति स्पष्ट है :--

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)	साक्षरता (प्रतिशत)	साक्षरता संख्या (लाखों में)	निरक्षर संख्या (लाखों में)
1951	160	8.02	13	147
1961	202	15.21	31	171
1971	258	19.07	49	209
1981	341	24.05	82	259

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। वर्तमान में अनुमानतः 60 लाख प्रौढ़ निरक्षर हैं। इसमें अधिकांश संख्या महिला वर्ग, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं शहरी कच्ची बस्तियों में रहने वालों की है। इस कार्यक्रम के द्वारा इन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राजस्थान में निम्न अभिकरण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं :–

1. राज्य सरकार
2. स्वैच्छिक संस्थायें

3. नेहरू युवक केन्द्र

4. विश्व विद्यालय/महाविद्यालय ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रशासन व्यवस्था :

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नेतृत्व का दायित्व केन्द्र सरकार का है। केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राज्य सरकारों को तकनीकी मामलों में परामर्श देता है। राजस्थान में राज्य स्तर पर निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना जयपुर में कार्यक्रम के प्रारम्भ से की गई है।

जिला स्तर पर 6 जिलों में क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू, भरतपुर में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं एवं अन्य जिलों में प्रौढ़ शिक्षा प्रायोजना अधिकारी/सहायक प्रायोजना अधिकारी कार्यक्रम को चलाने में जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता करते हैं । 30 केन्द्रों पर एक परिवीक्षक नियुक्त है जो केन्द्रों का निरन्तर परिवीक्षण करते हैं । प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर अध्यापन का कार्य अंशकालीन अनुदेशकों के द्वारा किया जाता है । अनुदेशक की नियुक्ति ऐसे स्थानीय व्यक्ति की, की जाती है जो इस कार्य में रुचि रखता हो तथा जिसे स्थानीय समुदाय का विश्वास भी प्राप्त हो । संलग्न चित्र से प्रशासन व्यवस्था और स्पष्ट हो जाती है :–

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (प्रशासन एवं व्यवस्था)

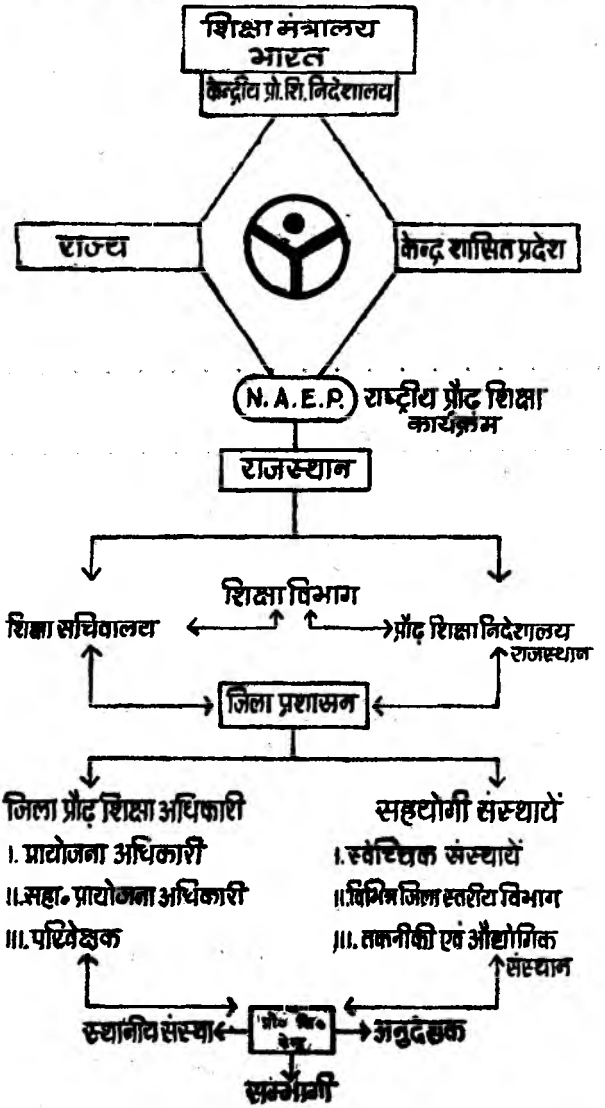

प्रशिक्षण एवं राज्य प्रौढ़ शिक्षा संदर्भ केन्द्र, जयपुर :

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं अध्ययन-अध्यापन संबंधी साहित्य का विशेष महत्व है। संदर्भ केन्द्र, जयपुर वातावरण निर्माण, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रम आदि में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रबोधन, मूल्यांकन, उत्तर साक्षरता व अनुवर्ती कार्यक्रम :

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र से परियोजना स्तर तक एवं जिला स्तर से प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर तक सूचनाओं का निरन्तर प्रवहन होता रहता है एवं उसी के आधार पर राज्य स्तर से प्रगति के त्रैमासिक आंकड़े भारत सरकार को भेजे जाते हैं।

केन्द्रों पर प्रौढ़ शिक्षार्थियों का मूल्यांकन वर्ष में दो बार किया जाता है। प्रथम मूल्यांकन केन्द्र प्रारम्भ होने के तीन माह की अवधि समाप्ति पर एवं द्वितीय मूल्यांकन 9 माह के पश्चात्।

मूल्यांकन विधियां अनौपचारिक रखी जाती हैं एवं अंक न देकर श्रेणी "अ", "ब" एवं "स" के अन्तर्गत मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षार्थी मूल्यांकन के अतिरिक्त, "राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम", का मूल्यांकन केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वाह्य संस्थान, "भारतीय प्रबंध

संस्थान अहमदाबाद" द्वारा कराया गया । संस्था की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत मानी गई है। विचार है कि कार्यक्रम मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखा जाय ।

उत्तर साक्षरता एवं अनुवर्ती कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण हैं । इसके द्वारा ही सीखने वालों की साक्षरता सुदृढ़ बनी रह सकेगी ।

राजस्थान में उत्तर साक्षरता के लिये प्रायोजना भारत सरकार से अभी स्वीकृत नहीं हुई है । निदेशालय अपने स्तर पर ही प्रत्येक जिले में कुछ चुने हुये केन्द्रों पर उत्तर साक्षरता का साहित्य उपलब्ध करा रहा है जिससे साक्षर प्रौढ़ वापिस निरक्षर न हो जाय ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अन्य विभागों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, सिंचाई, सहकारी विभाग, सामुदायिक विकास विभाग, जनसम्पर्क निदेशालय एवं लघु उद्योग विभाग से सामन्जस्य आवश्यक हैं । राज्य स्तर पर "आयोजना समन्वय समिति" के माध्यम से अन्य विभागों से सामन्जस्य किया जाता है ।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य

1. सामाजिक चेतना अर्थात अज्ञानता, शोषण एवं रूढ़िवादिता के विरुद्ध जागरूकता।

2. परिवार के लिये सह आर्थिक आधार पर स्रोत तैयार करना।

3. विकास की प्रक्रियाओं में भागीदार बनना।

4. लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान।

5. उपयोगी नागरिकता का निर्माण।

6. आत्मनिर्भरता का बोध।

7. क्रियात्मक साक्षरता एवं अंकगणित का बोध।

Sub. N... ...nal Systems Unit,
Nation... ...f Educational
Plann...
17-B,... ...,New Delhi-110016
DOC ....
Date ....

जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में मुद्रित। अगस्त, 81-5000.